झारखण्ड सरकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई0 गवर्नेस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची



संकल्प

विषय : Public Private Partnership (PPP) के आधार पर राँची में Indian Institute of Information Technology (IIIT) की स्थापना ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च्तर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अर्धसरकारी पत्र सं0–24-1/2008-TS.1, दिसम्बर 2010 के आलोक में राँची में IIIT की स्थापना के लिए M/s TCS Ltd., तथा M/s Tata Motors तथा M/S CCL, Ranchi को Industry Partner हेतु चयन किया गया। परियोजना राशि का 15% राशि, Industries partners द्वारा दी जाएगी।

2. कांके ब्लॉक मौजा सांगा, थाना—60 में 52.24 (37.24+15) एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की गई है तथा सू०प्रौ० एवं ई0—गवनेंस विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है जो मानव संसाधन विभाग, भारत सरकार के शर्त्त के अनुरूप है। इस भूमि के अलावे 14.40 एकड़ रैयती जमीन है उसे भी इस परियोजना के लिए चिन्हित है। रैयती जमीन की कीमत उपायुक्त, रांची को उपलब्ध करा दी गई है।



- 3. उक्त IIIT की स्थापना हेतु एक विस्तृत परियोजना तैयार कर मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भेजी गई थी। उक्त परियोजना का कुल कीमत रु० 128 करोड़ है। भारत सरकार, राज्य सरकार एवं इंडस्ट्रीज पार्टनरस 50:35:15 के अनुपात में राशि व्यय करेगी। इस परियोजना को मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक—D.No.-29-9/2012-TS-1 दिनांक 22.04.15 द्वारा IIIT, Ranchi की स्वीकृति पर सैद्वांतिक सहमति प्रदान की गई है। 20th Aug.14 को Site Selection Committee द्वारा उक्त Land को उपयुक्त पाया गया।
- 4. इस परियोजना पर भारत सरकार द्वारा Capital expenditure के रूप में व्यय हेतु कुल लागत रू० 128.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना पर भारत सरकार द्वारा उक्त कुल लागत का 50% अर्थात रू० 64.00 करोड़, राज्य सरकार द्वारा 35% अर्थात रू० 44.80 करोड़ तथा Industry Partners द्वारा 15% अर्थात रू० 19.20 करोड़ व्यय की जायेगी।
- 5. इस परियोजना पर Capital expenditure निम्नांकित मदों में इस प्रकार राशि प्रावधानित है:-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28.50 Cr.
Academic Construction Expenditure	
Residential Construction Expenditure	36.50 Cr.
Hostel Construction Expenditure	49.00 Cr.
Equipments Expenditure	6.25 Cr.
Furniture Expenditure	6.55 Cr.
Guest House Construction Expenditure	1.20 Cr.
Total	128.00 Cr.

(154)

इस संबंध में Board of Governance and Finance Committee द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। Additional Capital expenditure की अगर जरुरत पड़ी तो IIIT के लिए जो Donor (s) होंगे उनसे लिया जायगा तथा Research, Sponsorship तथा Promotional Activities से प्राप्त राशि भी Capital expenditure के रुप में व्यय की जा सकेगी। इस प्रकार राज्य सरकार को Capital expenditure के लिए अतिरिक्त राशि व्यय करने की संभावना नहीं बनती है।

- 6. Operating expenditure:- Faculty Development, Faculty and Staff Salaries, Infrastructure AMC तथा दूसरे प्रकार के व्यय (office expenditure) Operating expenditure में सम्मिलित होंगे। उक्त व्यय Tuition fee, Hostel Rent, Revenue through R&D, Consulting Service, Grantin-Aid from MHRD, GOI से प्राप्त राशि से वहन किया जायेगा। Donors, Research, Sponsorship तथा Promotion Activities से प्राप्त राशि से भी Operation cost पर वहन किया जा सकेगा। शुरु के तीन वर्षों में यानि 2016—17,2017—18 तथा 2018—19 तक IIIT deficit में रहेगा तथा चौथे वर्ष यानि 2019—20 में Profit में चला जायेगा। झारखण्ड में जो Corporate Office है, उनके turnover का 0.1% CSR के रुप में प्राप्त किया जायेगा। सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है जिसमें Capital expenditure एवं Operating expenditure का details अंकित है।
- 7. इस परियोजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर B.Tech in Electronics & Communication Engineering एवं B.Tech in Information Technology कोर्स की पढ़ाई होगी, जो चार वर्षों का होगा। प्रथम वर्ष के लिए क्रमशः 60–60 छात्रों का Intake होगा। Post Graduation की पढ़ाई तीसरे वर्ष से शुरू की जायेगी, जिसमें Master of Technology in Intelligent System, Master in Bio-Informatics, MBA in IT etc. की पढ़ाई होगी। इसमें कुल 3 छात्रों का intake होगा। Doctoral Programme के तहत PhD. के लिए research कार्य तीसरे वर्ष से शुरू की जायेगी। इसमें कुल 3 छात्रों का intake होगा। Bachelor Course में छात्रों का नामांकन AIEEE के माध्यम से होगा।
- 8. Faculty की नियुक्ति Faculty Recruitment Policy, AICTE, UGC की guidelines के तहत की जायेगी। शुरू में कुछ faculty outsource भी किये जायेंगे।
- 9. इस संस्थान में निम्नवत् Faculty में रिसर्च की सुविधाएँ होगी Human Computer Interaction, Bioinformatics, Wireless Communication, Microelectronics, Robotics, Software Engineering, Data Mining, Cloud Computing, GIS, Information Security etc.
- 10. IIIT Ranchi सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् एक निबंधित संस्था होगा तथा भारत सरकार, राज्य सरकार, Industry Partners के बीच MoU हस्ताक्षरित किये जायेंगे। संस्था के लिए Board of Governors गठित की जायेगी जो IIIT के लिए Executive body होगा।
- 11. MoU, MoA एवं Rule & Regulation का मुख्य अवयव निम्नवत् है:-

Board of Governors - The society will have a BOARD OF GOVERNORS (hereinafter called The BOARD) for The IIIT which would be the principal executive body of the institute having adequate administrative and financial powers. It would be

CK 414 17 15

entrusted with the task of managing the affairs of The IIIT. The composition of the Board and its powers and functions etc would be according to the terms and conditions spelt out in the Memorandum of Association and Rules and Regulations of the Society appended with this MOU.

However, the first chairperson of the Board shall be appointed by the First Party, in consultation with the Second Party and Third Party. The other members of the First Board of Governors, who are to be co-opted by the Board, shall be appointed by the Central Government in consultation with the Second Party and Third Party and the Chairperson.

- II) **Responsibility of State Gov.** i) State Govt. shall contribute 35% of the total capital cost of Rs. 128.00 Crore, for setting up of The IIIT;
- ii) Provide 50-100 acres of land, free of cost for setting up The IIIT, duly registered in the name of the Society.
 - iii) After signing of the MOU to forthwith have the Society registered under the relevant State Societies Registration Act.
- III) Responsibility of Industry Partners- To participate in The SCHEME, The THIRD PARTY has to
 - i) Nominate its representative as members for The BOARD.
 - ii) Contribute 15% of the total capital cost of Rs.128.00 crore for setting up of The IIIT. 50% of the money to be contributed by the Industry Partner(s) towards the scheme may be provided at the time of signing of the MOU in the form of an irrevocable Bank Guarantee in the name of the state Government from a Nationalized Bank by the Industry Partner(s). Once the MOA & Rules are framed and the IIIT is registered, the industry shall deposit the remainder 50% of its contribution in the name of the concerned IIIT. The remainder contribution would be made by the Industry Partner(s) depending upon the progress of the Scheme.
 - iii) to contribute towards research labs and projects, internship, faculty chairs etc., from time to time, in furthering the objects of THE SCHEME.

IV) Authorities of the Institute

The Following shall be the authorities of the Institute

- a. The Board of Governors.
 - b. The Chairperson of the Board
 - c. The Director of the Institute
 - d. The Senate Fig. Bost & minclesed & start FF Active Light Ele
 - e. The Research Council



- f. The Finance Committee
- g. The Registrar of the Institute
- h. Such Other Authorities appointed or nominated by the Board.

V) The Board of Governors

Composition of the Board

The Board shall be composed of the following members:

- I. Chairperson, ex -officio;
- II. A Member of the Central Govt. as well as State Govt.
- III. Two persons from the industry in the field of Information Technology, to be appointed by the institute on approval of a specific name by the Board from a panel of names recommended by the Industry Partners.
- IV. Two persons amongst faculty members of the institute to be nominated by the Chairperson in consultation with the Director and two senior-most Deans of the Institute:
- V. Two eminent research persons in the field of IT/ Allied fields to be co-opted by the Board.
- VI. Two persons having special knowledge of information technology, to be coopted by the Board.
- VII. Two senior-most Deans of the Institute, ex-officio;
- VIII. Director of Indian Institute of Technology, Patna / Kharagpur ex -officio;
- (Explanation. For the purposes of this clause, "zone" shall have the meaning assigned
- to it in the Explanation to section 11 of the Institutes of Technology Act, 1961)
- IX. Vice-Chancellor of Ranchi University, ex -officio;
- X. One person to represent the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes to be nominated from the area of Information Technology by the State Government;
- XI. Director of National Institute of Foundary and Forge Technology (NIFFT), Ranchi, ex -officio;
- XII. Director of the Institute who shall be the Member-Secretary of the Board, ex officio.
- 12. जब तक संस्थान की भवन—निर्माण का कार्य सम्पन्न नहीं हो जाता है तब तक NIFFT, Ranchi में पठन—पाठन का कार्य शुरू किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र 2016—17 से प्रारंभ की जायेगी।
- 13. MoU, MoA एवं Rule & Regulation में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई संसोधन किया जाता है तो उसे पुनः मंत्रिपरिषद के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे MoU, MoA एवं Rule & Regulation में यथोचित समावेश कर लिया जायेगा।



14. PPP Module पर राँची में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) की स्थापना एवं संलग्न MoU(अनुलग्नक–A),MoA(अनुलग्नक–B),एवं Rules & Regulation की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक–2973 दिनांक 07.12.15 के कम में दिनांक 08.12.15 की बैठक के मद सं0–24 में दी गई है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण के सूचनार्थ झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(सुनील कुमार वर्णवाल) सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-सू०प्रौ० / IIIT-Estt.-65/2013 310 6

राँची,दिनांक:- 22 12 15

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/जिला उपायुक्त, राची/ई-गजट के विभागीय नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:-सू०प्रौ०/IIIT-Estt.-65/2013 3106

राँची,दिनांक:-22 12 13

प्रतिलिपि:— सहायक अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस संकृत्प को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित कर राजपत्र की 200 प्रतियाँ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उपलब्ध करा दी जाय।

सरकार के सचिव